1	2	3
15	Meghalaya	15,875
16	Mizoram	18,853
17	Nagaland	14,321
18	Orissa	47,205
19	Punjab	1,343
20	Rajasthan	12,835
21	Sikkim	3,033
22	Tamilnadu	17,713
23	Tripura	5,535
24	Uttar Pradesh	33,609
25	West Bengal	8,015
26	Andaman and Nicobar	7,622
27.	Chand garh	5
28	Dadra & Nagar Haveli	206
29	Daman & Diu	2
30	Delhi	22
31	Lakshadweep	—
32	Pondicherry	—
	TOTAL :	6,39,182

Ganga Action Plan

2081. SHRI KRISHNA KUMAR. BIRLA : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government have converted the Ganga Action Plan into a proposed National River Action Plan ;

(b) if so, the purpose of converting the same ;

(c) whether the National River Action Plan would be equipped with more powers ; and

d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) to (d) A National River Action Plan for abatement of pollution in the identified polluted stretches of some major rivers of the country is under formulation. Details in this regard are being worked out.

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का गठित किया जाना

2082. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में परती भूमि को विकसित करने के लिए 1985 में एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह बोर्ड अपने दायित्वों का निभाने में विफल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में परती भूमि के विकास में बोर्ड की विफलताओं पर विचार करने के बाद मई, 1992 में एक नयी योजना बनाने पर विचार किया गया है, और यदि हां, तो देश में परती भूमि को विकसित करने के लिए भावी कार्यक्रम क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना मई, 1985 में की गई थी और इसे जन-सहयोग से वनीकरण और वृक्षारोपण के वृहत कार्यक्रम के माध्यम से बंजर भूमि का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था । सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान देश में कुल 8.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए । पहले की सभी योजना अवधियों (1950-1985) में कुल 8.2

मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर ये कार्यकलाप चलाए गए थे । वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमश: 1.4 मिलियन हेक्टेयर तथा 1.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए । आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम में विस्तार किए जाने की संभावना है । तथापि इस संबंध में मई, 1992 में एक नई योजना पर विचार किया गया था ।

लम्बित परियोजनाओं की मंजूरी

2083. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेकों परियोजनायें मंजूरी के लिए सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाओं को मंजूरी की प्रतीक्षा है ;

(ग) कितनी परियोजनायें छ: महीनों से अधिक अवधि से मंजूरी के लिए लंबित हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि परियोजनाओं की मंजूरी में विलम्ब से देश की विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार परियोजनाओं की मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई प्रभावकारी कदम उठाने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजी गई 1752 परियोजनाओं में से इस समय केवल 65 परियोजनायें लंबित हैं । इनमें से 39 परियोजनायें 20 महीने से भी अधिक समय से लंबित हैं । इसी प्रकार वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त 4,973 परियोजनाओं में से केवल 182 परियोजनाएं लंबित हैं और ये सभी छह मास से कम समय से लंबित हैं ।

(घ) से (ङ) केवल उन्हीं मामलों में परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब होता है जिनके संबंध में अपेक्षित आंकड़े और कार्य योजनायें तैयार नहीं होती हैं। अन्यथा पूरे पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य-योजनाएं प्राप्त होने पर ही पर्यावरण के संबंध में तीन मास के अंदर तथा वन भूमि को उपयोग में लाने के मामले में एक साल के भीतर परियोजनाओं पर निर्णय ले लिया जाता है । मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ परस्पर सम्पर्क बनाए रखा जाता है ।

गंगा कार्य योजना

2084. **श्री राम नरेश यादव :**
क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गंगा के किनारे वाले किन-किन शहरों को गंगा कार्य योजना के अधीन लाया जाएगा ;

(ख) उस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(ग) उन शहरों के प्रदूषण को कितना नियंत्रित किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के इस समय चल रहे पहले चरण के अंतर्गत शामिल किए गए गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों के नाम विवरण में दिए गए हैं । गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) गंगा कार्य योजना के पहले चरण की स्कीमों के संदर्भ में आठवीं पंचवर्षीय योजना में संभावित अनुमानित व्यय लगभग 130 करोड़ रुपए है ।

(ग) गंगा कार्य योजना के पहले चरण की स्कीमों के पूरा हो जाने पर कुल 873 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशेष जल के अवरोधन, दिशा- परिवर्तन और उपचार किए जाने की आशा है ।